उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

जमानत याचिका संख्या 253 वर्ष 2021

अखिलेश मोहन बहुगुणा बनाम उत्तराखंड राज्य

अखिलेश मोहन बहुगुणा.....आवेदक

उत्तराखण्ड राज्य.....प्रतिवादी

प्रतिवादी श्री शक्ति सिंह

आवेदक/समझौते के वकील श्री दिनेश चौहान,

ब्रीफ होल्डर, उत्तराखंड राज्य के लिए।

माननीय शरद कुमार शर्मा, जे

यह जमानत का दूसरा आवेदन है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 323, 504, 506 और 34 के तहत अपराधों में कथित संलिप्तता के लिए पहली जमानत याचिका, जो 2019 के केस क्राइम नंबर 19 के माध्यम से रानीपोखरी, जिला देहरादून पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, को इस अदालत ने 24 जून 2019 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया है।

2. आवेदक के वकील ने दूसरी जमानत याचिका पर बहस की थी, वास्तव में जैसे कि यह एक नया तर्क था, जिस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता थी, आवेदक– अखिलेश मोहन बहुगुणा की दूसरी जमानत याचिका पर विचार करते समय, हालांकि, कुछ अपवादों के साथ, उन निर्णयों के आधार पर, जिन पर उन्होंने भरोसा किया था, इस दूसरी जमानत याचिका पर बहस करते हुए–

3. निर्णयों से निपटारे से पहले, और विशेष रूप से, आवेदक के वकील ने दूसरी जमानत याचिका पर बहस की थी, वास्तव में जैसे कि यह एक नया तर्क था, जिस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता थी, आवेदक – अखिलेश मोहन बहुगुणा की दूसरी जमानत याचिका पर विचार करते समय, हालांकि, कुछ अपवादों के साथ, उन निर्णयों के आधार पर, जिन पर उन्होंने भरोसा किया था, इस दूसरी जमानत याचिका पर बहस करते हुए आवेदक के विद्वानों द्वारा निर्णयों से निपटने से पहले, और विशेष रूप से, आवेदक के विद्वान वकील के तर्क का जवाब देने के लिए, जिस पर यह न्यायालय न्यायिक रूप से विचार करने और प्रत्येक तर्क का उत्तर देने के लिए बाध्य है, कि क्या एफआईआर में अपराध की शिकायत के लिए आवेदक के लिए स्पष्ट मन और पूर्वनियोजित इरादा था। क्या यह अपने आप में अपवादों को निकालने के लिए था या नहीं, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले द्वारा बनाया गया है, जिसे आवेदक के विद्वान वकील द्वारा आधारित किया गया है। इस न्यायालय का विचार है कि एफआईआर की सामग्री की सराहना स्वयं पहले प्रासंगिक हो जाती है।

4. एफआईआर के शिकायतकर्ता श्री विजय शर्मा, जो घटना के चश्मदीद गवाह भी थे, क्योंकि वह मौके पर मौजूद थे, और विशेष रूप से, यदि आरोपों को ध्यान में रखा

जाता है, जब घटना 28.05.2020 को 22.22 बजे हुई है, वास्तव में यदि एफआईआर में दिए गए शिकायतकर्ता के बयान को ध्यान में रखा जाता है–

> ''उसके पति, देवर व सास झगडा व गाली–गलौच और मारपीट कर रहे है जिस पर मैं अपनी बडी बहन सरस्वती के साथ मोटर साईकिल में व मेरा बडा भाई अजय शर्मा दूसरी मोटरसाईकिल में अपनी बहन के ससुराल पहुॅचे, तो हमने देखा मेरी बहन अर्चना बहुगुणा को उसके पति मुकेश मोहन बहुगुणा व सास मारपीट कर रहे हैं, उसके पास उसका देवर अखिलेश मोहन बहुगुणा मेरी बहन की तरफ बन्दूक तान कर खडा है, उसका पति और सास ने उसके देवर को कहा कि इसको गोली मार दो किस्सा यहीं खत्म कर दो जिस पर तीनों भाई–बहन बीच–बचाव करते हुए अपने बहन को छुडाने उसके समीप जाने लगे, तो मेरी बहन की सास व पति ने उसके देवर को कहा कि इसको मारने से पहले इन तीनों को जान से मार दें, जिस पर मेरी बहन के देवर ने कहा कि तुम लोग सही कर रहे हो पहले में इन तीनों का काम तमाम कर देता हूॅ और कहते हुये जान से मारने की नियत से हम तीनों की तरफ बन्दूक तानकर गोली चला दी, जिस पर मेरे बडे भाई अजय शर्मा के पेट में गोली लग गयी और वह वही जमीन पर गिर गया और उसके पेट से खून आने लग गया, मैं और मेरी बहन अपने भाई अजय शर्मा को घायल अवस्था में हिमालयन हॉस्पिटल ले गये जहॉ उसे इमरजेंसी में भरती करा दिया जहॉ मेरा भाई अभी भी बेहोश है। अतः महोदय से निवेदन है''

एफआईआर में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बहनोई ने ये शब्द कहे हैं कि दोनों भाई, जो अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी बहन के ससुराल गए थे। बहनोई ने जानबूझकर इस आशय से बयान किये थे कि आवेदक के भाई ने कहा कि 'पहले इन लोगों को गोली मार दो। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान आवेदक के भाई द्वारा दिए गए बयान/निर्देशों पर आवेदक द्वारा इस कृत्य को करने के लिए जानबूझकर प्रेरित किया गया था, और यह केवल इतना ही नहीं है कि यह आगे की शिकायत है कि वर्तमान आवेदक ने कहा है कि "तुम लोग सही कह रहे हो पहले में लोगों का काम तमाम कर देता हूं। "। एफआईआर का यह हिस्सा और आवेदक द्वारा दिए गए कथन, एक स्पष्ट ज्ञान, और इरादे और पूर्व नियोजित कार्य को दर्शाता है, जिसमें पीड़ित पर चोट पहुंचाने के इरादे से गोली चलाई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप गोली लगी थी। इसका मतलब है, जब आवेदक के भाई द्वारा निर्देश दिए गए थे, अर्चना के परिवार के सदस्यों को दूर करने के लिए, जो अर्चना के ससुराल वालों के निवास पर गए थे, और अर्चना के भाई पर आवेदक द्वारा गोली चलाने के वास्तविक कृत्य के घटने से पहले, पर्याप्त समय अंतराल था। जो दुखद निधन का सामना कर चुके हैं। इसका अर्थ है, एक बार जब किसी कार्य को करने के लिए जानकारी एकत्र करने के बीच समय का अंतर होता है, और जहां इसके जवाब में कोई कार्रवाई होती है, तो किसी कार्य को करने के लिए प्रतिबद्ध होने के दिमाग का उपयोग आवेदक को इसके परिणामों को जानने के लिए अच्छी तरह से किया गया था, इसका मतलब है कि आवेदक सचेत था और पूर्वनियोजित इरादों के साथ सक्रिय था, फायरिंग के कृत्य के परिणामी प्रभाव के बारे में जानकर जिसके कारण अजय शर्मा को दुखद निधन का सामना करना पड़ा था।

5. एफआईआर में शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि जब वह शिकायतकर्ता और पीड़िता की बहन के खिलाफ किए जा रहे अत्याचारों के बारे में सूचना मिलने पर घटनास्थल पर गया, तो शिकायतकर्ता ने कहा है कि उसकी बहन अर्चना का बहनोई, यानी अखिलेश मोहन बहुगुणा, यानी वर्तमान आवेदक खड़ा था और पहले से ही अर्चना की ओर बंदूक तान रहा था। आवेदक के पास, अर्चना के पति, उसका भाई भी अर्चना की सास के साथ खड़ा था।

6. एफआईआर में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बहनोई ने ये शब्द कहे हैं कि दोनों भाई, जो अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी बहन के ससुराल गए थे 3 ससुराल वालों के अत्याचार, बहनोई ने जानबूझकर बयान दिए थे, इस आशय से कि आवेदक के भाई ने कहा कि 'पहले लोगों को गोली मारदो'। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान आवेदक के भाई द्वारा दिए गए बयान/निर्देशों पर आवेदक द्वारा इस कृत्य को करने के लिए जानबूझकर प्रेरित किया गया था, और यह केवल इतना ही नहीं है कि यह आगे की शिकायत है कि वर्तमान आवेदक ने कहा है कि "तुम लोग सही कह रहे हो पहले में लोगों का काम तमाम कर देता हूं। "। एफआईआर का यह हिस्सा और आवेदक द्वारा दिए गए कथन, एक स्पष्ट ज्ञान, और इरादे और पूर्व नियोजित कार्य को दर्शाता है, जिसमें पीड़ित पर चोट पहुंचाने के इरादे से गोली चलाई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप गोली लगी थी। इसका मतलब है, जब आवेदक के भाई द्वारा निर्देश दिए गए थे, अर्चना के परिवार के सदस्यों को दूर करने के लिए, जो अर्चना के ससुराल वालों के निवास पर गए थे, और अर्चना के भाई पर आवेदक द्वारा गोली चलाने के वास्तविक कृत्य के कमीशन से पहले, पर्याप्त समय अंतराल था। जो दुखद निधन का सामना कर चुके हैं। इसका अर्थ है, एक बार जब किसी कार्य को करने के लिए जानकारी एकत्र करने के बीच समय का अंतर होता है, और जहां इसके जवाब में कोई कार्रवाई होती है, तो किसी कार्य को करने के लिए प्रतिबद्ध होने के दिमाग का उपयोग आवेदक को इसके परिणामों को जानने के लिए अच्छी तरह से किया गया था, इसका मतलब है कि आवेदक सचेत था और पूर्वनियोजित इरादों के साथ सक्रिय था, फायरिंग के कृत्य के परिणामी प्रभाव के बारे में जानकर जिसके कारण अजय शर्मा को दुखद निधन का सामना करना पड़ा था।

7. इसलिए, यह न्यायालय आवेदक द्वारा दी गई दलीलों से सहमत नहीं है, कि अपराध करने का कोई पूर्व नियोजित इरादा नहीं था, स्पष्ट रूप से और अस्थायी रूप से केवल इस दूसरे जमानत आवेदन पर विचार करने के प्रयोजनों के लिए, मेरा विचार है कि एफआईआर में किए गए स्पष्ट रूप से विशिष्ट कथनों को ध्यान में रखते हुए, भाई के कथनों से प्रेरित झुकाव के साथ एक स्पष्ट झुकाव था, जो दर्शाता है, कि यह अजय पर गोली चलाने का एक सचेत कार्य था, जिसने बाद में चोटों के कारण दम तोड़ दिया, इसलिए अंतिम परिणामों का ज्ञान आवेदक के ज्ञान में अच्छी तरह से था, जो किए गए कार्यों के कालक्रम से स्पष्ट है। आवेदक द्वारा।

8. आवेदक के वकील द्वारा दूसरा तर्क, जिस पर निष्कर्ष आमंत्रित किए गए थे, वह यह है कि मुकदमे में देरी होने की संभावना है और आवेदक को मुकदमे की लंबी कार्यवाही के दौरान अनिश्चित काल के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता है, जिसे पर्याप्त समय लगने के बाद समाप्त होना है। और चूंकि आवेदक 29 मई 2020 से जेल में बंद है, इसलिए मुकदमे की अवधि और संभावित समय जो इसमें लगेगा, उसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि आवेदक को जमानत देने पर विचार करने के कारकों में से एक है।

9. इस न्यायालय का विचार है कि निरपवाद रूप से सभी आपराधिक और यहां तक कि सिविल मामलों में भी, जहां मुकदमे में पर्याप्त समय लगने वाला है, हालांकि रिकॉर्ड पर रखी गई किसी भी सामग्री के बिना तत्काल मामले में पकड़ा गया है, इसे हमेशा एक सामान्य मानदंड के रूप में नहीं लिया जा सकता है, जिसे मामलों की परिस्थितियों के बावजूद सभी मामलों में अनिवार्य रूप से लागू किया जा सकता है। और यह कि केवल मुकदमे में पर्याप्त समय लगने वाला है, यह हमेशा आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा होने का आधार नहीं हो सकता है, अधिकार के मामले के रूप में, और वह भी जहां यह जघन्य अपराध से संबंधित है, जिसके लिए ज्ञान, इरादा, कार्रवाई और निर्देशों पर प्रतिक्रिया एक दूसरे के लिए एकजुट हैं।

10. विद्वान वकील का यह तर्क इस तथ्य पर आधारित है, कि जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए आरोप–पत्र के अनुसार, 23 अगस्त 2020 को 2020 का चार्जशीट नंबर 32 होने के नाते, 22 गवाह हैं, जिनसे ट्रायल कोर्ट द्वारा पूछताछ की जानी है। यह एक स्वीकृत मामला है, जिसे आवेदक के वकील द्वारा तर्क दिया गया है, कि अब तक केवल तीन गवाहों से पूछताछ की गई है, और शेष 19 गवाहों से ट्रायल कोर्ट द्वारा पूछताछ की जानी बाकी है।

11. इन घटनाओं में, जहां एक ऐसे मामले में जहां एफआईआर में आवेदक को एक विशिष्ट भूमिका सौंपी गई है, जहां कथन स्पष्ट रूप से दिखाता है और स्पष्ट रूप से अपराधों के निर्माण में आवेदक की प्रत्यक्ष भागीदारी को इंगित करता है, जहां अपराधों के चश्मदीद गवाह हैं , जो सीधे अपराध में शामिल होने के लिए जिम्मेदार हैं, और वह भी विशेष रूप से, जब मृतक का पोस्टमॉर्टम किए जाने के बाद, और एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार भी, आवेदक के कब्जे से पाई गई बंदूक का उपयोग भी अपराधों के लिए किया गया था। मुकदमे के समापन में शामिल होने की संभावना वाली अवधि को सभी परिस्थितियों में आवेदक को जमानत पर रिहा करने का एक कारण नहीं माना जा सकता है, और वह भी विशेष रूप से जब मुकदमे के प्रमुख गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है, और एक घटना में यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना हो सकती है, वर्तमान मामले में इनकार नहीं किया जा सकता है, जहां अब तक रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य प्रथम दृ

ष्टया स्थापित करते हैं, कि आवेदक का अपराध करने में सीधा संबंध और भागीदारी है, जैसा कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों से विदित है।

12. अपराध में आवेदक की भागीदारी को कम करने के लिए आवेदक के वकील द्वारा तर्क आमंत्रित किए गए तर्क का एक अन्य अंग, जो आवेदक के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया है, यह है कि अजय शर्मा पर गोली चलाने का कार्य हाथापाई, हाथापाई के आक्रोश के रूप में था। जो दो परिवार के सदस्यों के बीच हुआ है, और यह तर्क दिया गया है कि आवेदक को भी हाथापाई में चोटें आईं, हालांकि आवेदक को लगी चोटों की प्रकृति को साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय सामग्री नहीं है, इसलिए कोई चिकित्सा दस्तावेज नहीं होने के कारण, रिकॉर्ड पर लाया जा रहा है। बल्कि आवेदक के वकील द्वारा जो प्रयास किया गया है, वह मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए था, जिसे 2020 के पहले जमानत आवेदन संख्या 2183 में प्रस्तुत किया गया था, उक्त मेडिकल रिपोर्ट श्री मुकेश मोहन बहुगुणा की मेडिकल रिपोर्ट है, न कि वर्तमान आवेदक की। इसलिए, उक्त मेडिकल रिपोर्ट को वर्तमान आवेदक के लिए एक मेडिकल रिपोर्ट के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है, ताकि यह दिखाया जा सके कि हाथापाई हुई थी, जिसके कारण आवेदक को भी चोट लगी थी, चोट या मेडिकल रिपोर्ट के रिकॉर्ड पर रखे जाने के अभाव में, जो आवेदक से संबंधित है।

13. इस "हाथापाई" का आरोप, जिसे आवेदक के वकील द्वारा एक सामान्य तर्क के तहत तर्क दिया गया है, यदि एफआईआर की सामग्री को ध्यान में रखा जाता है, वास्तव में अपराध होने से पहले भी, पक्ष किसी भी हाथापाई में प्रवेश कर सकते थे । वास्तव में, आवेदक को अलग–थलग रखा गया था , जिसमें पहले से ही अर्चना की ओर इशारा करने वाली बंदूक थी, और चूंकि हाथापाई का कोई सिद्धांत नहीं है, जिसकी कभी शिकायत की गई थी और न ही जांच में पाया गया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि भले ही हाथापाई हुई थी, आवेदक इसमें शामिल था। और वह घायल हो गया था, क्योंकि उस समय आवेदक मृतक से काफी दूर था, और पहले से ही अर्चना पर बंदूक तानने के कार्य में शामिल था।

14. आवेदक के वकील ने इस मामले में यह भी तर्क दिया था कि यदि आईपीसी की धारा 300 के तहत निहित प्रावधान, जो "हत्या" को परिभाषित करते हैं, यदि उस पर विचार किया जाता है, तो दूसरा अपवाद यानी चोट पहुंचाना और जहां अपराधी को पता है कि किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है, जिसे नुकसान पहुंचाया गया है, एक तथ्य है, जिसे पहले ही ऊपर संदर्भित किया जा चुका है, और इसलिए, आवेदक का कार्य, जिसे पहले ही अनुमान लगाया जा चुका है और ऊपर निपटाया गया है कि यह एक इच्छित कार्य है, और यह शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से था और एक बार जब यह बन्दूक के कारण हो रहा है, जिसे आवेदक द्वारा ले जाया जा रहा था, इरादा स्वयं अधिनियम से स्पष्ट है, और आवेदक द्वारा किए गए कथनों पर की गई कार्रवाई, जो

एफआईआर में परिलक्षित होती है।

15. इसलिए, आईपीसी की धारा 300 की व्याख्या करते हुए आवेदक के वकील द्वारा जिस अपवाद को उजागर करने की मांग की गई थी, इस न्यायालय का विचार है कि चोटों की प्रकृति, इरादा, कार्य, क्योंकि यह सीधे तौर पर दिमाग के निर्णायक झुकाव की ओर ले जाता है, और आग्नेयास्त्र के कारण हुआ है। जिसका उपयोग प्रथम सूचना रिपोर्ट में और साथ ही चश्मदीद गवाहों द्वारा साबित किया गया था, आवेदक के अपराध की प्रकृति को सीधे आईपीसी की धारा 300 के दूसरे खंड के तहत लाएगा।

16. जमानत पर रिहा होने की अपनी याचिका का समर्थन करने के लिए आवेदक के वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "भारत संघ बनाम केए नजीब" के मामलों में प्रदान की गई एक न्यायिक मिसाल का उल्लेख किया है, जैसा कि 2021 (खंड 3) एससीसी 713 में बताया गया है, और विशेष रूप से, उन्होंने पैराग्राफ संख्या 10 का उल्लेख किया है तथा पैरा संख्या 12, 15, 16, 18 और 20 का उल्लेख भी किया है। उपरोक्त वर्णित **पैराग्राफ संख्या 10** यहां दिया गया है– पैरा संख्या "10 यह एक तथ्य है कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में प्रतिवादी के दोषी होने या नहीं होने की संभावना निर्धारित नहीं की है, या यूएपीए की धारा 43–डी (5) की कठोरता उसके लिए विदेशी है या नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने लंबी अवधि की कैद और निकट भविष्य में किसी भी समय मुकदमे की संभावना पूरी होने के कारण जमानत देने की अपनी शक्ति का उपयोग किया है। उच्च न्यायालय द्वारा सौंपे गए कारण स्पष्ट रूप से हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़े हैं, निश्चित रूप से यूएपीए की धारा 43–डी (5) द्वारा बनाए गए वैधानिक प्रतिबंध को संबोधित किए बिना। **पैराग्राफ संख्या–12** यहां तक कि आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 या नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 ("एनडीपीएस") जैसे विशेष कानूनों के मामले में भी, जिसमें जमानत देने के लिए कुछ कठोर शर्तें हैं, परमजीत सिंह बनाम अन्य मामलों में इस अदालत ने मामला दर्ज किया है। राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली), बब्बा बनाम दिल्ली महाराष्ट्र राज्य (2005) और उमरमिया बनाम। गुजरात राज्य ने अभियुक्तों को जमानत पर बढ़ा दिया जब वे एक विस्तारित अवधि के लिए जेल में थे और मुकदमे के जल्द पूरा होने की बहुत कम संभावना थी। इस प्रकार इस तरह के विशेष अधिनियमों में जमानत के लिए कठोर शर्तों की संवैधानिकता को मुख्य रूप से निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित परीक्षणों की कसौटी पर उचित ठहराया गया है। **पैराग्राफ संख्या–15** इस न्यायालय ने कई निर्णयों में स्पष्ट किया है कि संविधान के भाग–3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता न केवल उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता बल्कि न्याय और त्वरित परीक्षण तक पहुंच को भी इसके सुरक्षात्मक दायरे में कवर करेगी। विचाराधीन कैदियों का प्रतिनिधित्व करने वाली सुप्रीम कोर्ट कानूनी सहायता समिति भारत संघ एमएएनयू/एससी/0877/1994: (1994) 6 एससीसी 731, पृष्ठ 15, यह माना गया कि

विचाराधीन कैदियों को मुकदमे के लंबित रहने तक अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। आदर्श रूप से, किसी भी व्यक्ति को अपने कृत्यों के प्रतिकूल परिणामों का सामना नहीं करना चाहिए जब तक कि इसे तटस्थ मध्यस्थ के समक्ष स्थापित नहीं किया जाता है। हालांकि, वास्तविक जीवन की व्यावहारिकता के कारण जहां एक प्रभावी परीक्षण को सुरक्षित किया जाए और किसी संभावित अपराधी को बड़े पैमाने पर लंबित परीक्षण में छोड़ दिए जाने की स्थिति में समाज के लिए जोखिम को कम किया जाए, अदालतों को यह तय करने का काम सौंपा जाता है कि किसी व्यक्ति को मुकदमे के लंबित रहने तक रिहा किया जाना चाहिए या नहीं। एक बार यह स्पष्ट है कि 8 समय पर मुकदमा चलाना संभव नहीं होगा और अभियुक्त को एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए कैद का सामना करना पड़ा है, अदालतें आमतौर पर उन्हें जमानत पर बढ़ाने के लिए बाध्य होंगी। **पैराग्राफ संख्या–16** एनआईए बनाम जहूर अहमद शाह वटाली (सुप्रा) मामले में फैसले के संबंध में , जिसे एएसजी ने उद्धृत किया था, हम पाते हैं कि यह पूरी तरह से अलग तथ्यात्मक मैट्रिक्स से संबंधित है। उस मामले में, उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत के निष्कर्ष को पलटने के लिए रिकॉर्ड पर मौजूद सभी सबूतों की फिर से सराहना की थी कि वे प्रथम दृष्टया दोषसिद्धि और जमानत की सहवर्ती अस्वीकृति का मामला हैं। उच्च न्यायालय ने व्यावहारिक रूप से एक मिनी–ट्रायल किया था और कुछ सबूतों की स्वीकार्यता निर्धारित की थी, जो जमानत याचिका के सीमित दायरे से अधिक थी। यह न केवल धारा 43–डी (5) के तहत प्रथम दृष्टया मूल्यांकन के वैधानिक जनादेश से परे था, बल्कि यह समय से पहले था और संभवतः मुकदमे को पूर्वाग्रह से ग्रस्त करता। इन परिस्थितियों में इस न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और जमानत रद्द कर दी। **पैराग्राफ संख्या– 18** मामले को ध्यान में रखते हुए, हम इस तथ्य से अवगत हैं कि प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं और सामाजिक सद्भाव के लिए एक गंभीर खतरा हैं। अगर यह दहलीज पर एक मामला होता, तो हम प्रतिवादी की प्रार्थना को सिरे से अस्वीकार कर देते। हालांकि, हिरासत में उनके द्वारा बिताई गई अवधि की लंबाई और जल्द ही पूरी होने वाली सुनवाई की संभावना को ध्यान में रखते हुए, ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय के पास जमानत देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। अपीलकर्ता के अपनी पसंद के साक्ष्य का नेतृत्व करने और किसी भी संदेह से परे आरोपों को स्थापित करने के अधिकार के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है और साथ ही हमारे संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत प्रतिवादी के अधिकारों को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। **पैराग्राफ संख्या– 20** उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, हम आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, हमें लगता है कि प्रतिवादी को रिहा करते समय ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के अलावा, यह न्याय और समाज के सर्वोत्तम हित में होगा कि कुछ अतिरिक्त शर्तें लगाई जाएं कि प्रतिवादी हर हफ्ते सोमवार को सुबह 10 बजे स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति

दर्ज कराएगा और लिखित में सूचित करेगा कि वह किसी अन्य नए अपराध में शामिल नहीं है। प्रतिवादी ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग लेने से भी बचेगा जो सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का सकती है। यदि प्रतिवादी को अपनी जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने, गवाहों को प्रभावित करने या किसी अन्य तरीके से मुकदमे को बाधित करने का प्रयास किया जाता है, तो विशेष अदालत को रद्द करने की स्वतंत्रता होगी। ऐसे में उसकी जमानत तुरंत। तदनुसार उपरोक्त निर्देशों के अधीन अपील को खारिज किया जाता है।

17. सबसे पहले, जिन अपराधों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पर विचार करने के प्रयोजनों के लिए प्रयोग पर विचार किया जा रहा था, उन अपराधों के संबंध में था, जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा था, वे धारा 143, 147, 148, 120 बी, 341, 427, 323, 324, 326, 506 भाग 2, आईपीसी की धारा 201, 202, 153 ए, 212, 307 और 149, और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3 और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 की धारा 16, 18, 18 बी, 19 और 20।

18. आवेदक के विद्वान वकील ने केए नजीब (सुप्रा) के फैसले के पैराग्राफ संख्या 10 का उल्लेख करते हुए विशेष रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई अभिव्यक्ति के उपयोग पर जोर दिया है, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने आवेदक के पहलू को निर्धारित नहीं किया है क्योंकि प्रतिवादी के अपराधों के लिए दोषी होने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। वास्तव में, यदि **पैराग्राफ संख्या 10** के निहितार्थ को ध्यान में रखा जाता है, तो उस मामले के संदर्भ में यह एक ऐसा मामला था जहां उच्च न्यायालय के आदेश, जहां इस पर विचार किया जा रहा था, क्या उच्च न्यायालय ने इस आशय के निष्कर्ष को दर्ज नहीं किया है कि जमानत के लिए आवेदक और निर्धारण से संबंधित पहलू, गंभीर अपराधों को अंजाम देने में शामिल होने की संभावना के बारे में आवेदक के पास जो कुछ भी था, वह एक ऐसा तथ्य था जिसकी कमी थी और उच्च न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया था, जहां उच्च न्यायालय ने जमानत देने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग केवल लंबे समय तक अवतार के कारण किया है, और निकट भविष्य में मुकदमे की निष्पक्षता के कारण किया।

19. इसके अलावा, आवेदक के वकील ने उक्त निर्णय के **पैराग्राफ संख्या 12** का उल्लेख करते हुए, वास्तव में अदालत को यह समझाने की कोशिश की है कि आतंकवादी और बाधित गतिविधि रोकथाम अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम के तहत जघन्य अपराधों के लिए, जो भी मुकदमे के लिए और जमानत देने के लिए कठोर शर्तों को लागू करने पर विचार करते हैं, जमानत पर आवेदक का विस्तार, **पैराग्राफ संख्या– 10 में वर्णित विस्तारित अवधि से यह आशय है कि** जब मुकदमे में कुछ अधिक समय लगने की उम्मीद है, और निकट भविष्य में मुकदमे के पूरा होने की कोई संभावना

नहीं है, अदालत ने अपनी राय व्यक्त की है, कि आवेदक को हिरासत में रखना बहुत कठोर होगा, क्योंकि त्वरित परीक्षण की संभावना नहीं है। और वह भी तब, जब माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हिरासत में रखे जा रहे निर्दोष नागरिकों की रक्षा करने के स्पष्ट इरादे से यह टिप्पणी की गई थी, हालांकि इसमें तर्क निर्णायक नहीं था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में, आवेदक की संलिप्तता की बेगुनाही एक पहलू नहीं है, जिसे इस स्तर पर इस न्यायालय ने, मैं इस मामले में दखल देना चाहता हूं, क्योंकि यह शिकायत में ही स्पष्ट रूप से और विस्तार से दिया गया है, और ऊपर दिए गए कारणों के लिए, विशेष रूप से, जब घटना के प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, बयान होते हैं, और बयान पर कार्रवाई होती है। इसलिए, निर्दोषता का कोई स्पष्ट तत्व नहीं होने के अभाव में, यह हो सकता है कि जिस जमानत पर विचार किया जा रहा है वह गंभीर अपराधों के संबंध में थी, यह हमेशा सभी परिस्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता है, चाहे जिस मामले में अपराध किए गए हों।

20. इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता, जिसके प्रभाव को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय के **पैराग्राफ संख्या 15** में संदर्भित किया गया है, जिसे आवेदक के विद्वान वकील द्वारा आधारित किया गया है, इस प्रकार किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने का इरादा रखता है, लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की अनन्य अवधारणा एक निरंकुश अवधारणा नहीं है, और ऐसा नहीं है, कि कानून के तहत इसे मामले की परिस्थितियों और अपराध के कृत्य में किसी व्यक्ति की भागीदारी के आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता है, जहां हमेशा सभी परिस्थितियों में गंभीरता के बावजूद। अपराध के लिए, स्वतंत्रता हमेशा आवेदक को जमानत पर रिहा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, और वह भी वर्तमान मामले में जब कुल 22 गवाहों में से केवल तीन गवाहों से पूछताछ की गई है, और जमानत पर आवेदक की रिहाई की स्थिति में, और विशेष रूप से, जब उसकी भागीदारी सीधे जिम्मेदार और स्पष्ट है। लगाए गए आरोपों और जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को देखते हुए, सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना हो सकती है, जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रमुख गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है।

21. आवेदक के वकील ने फैसले के **पैराग्राफ संख्या 18** का संदर्भ देते हुए प्रस्तुत किया है कि जमानत आवेदन को अपराध की गंभीरता और सामाजिक सद्भाव को खतरे में डालने की संभावना के बारे में इसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य से विचार किया जाना चाहिए, जो उक्त मामले में विषय वस्तु थी, जहां जिस अपराध की सुनवाई की जा रही थी, वह आईपीसी की धारा 147, 148 143 और 120 बी के तहत अपराध थे। यह वर्तमान मामले में प्रचलित समान स्थिति नहीं हो सकती है, क्योंकि यह एफआईआर में किए गए विशिष्ट कथन थे, और इसमें लगाए गए आरोप, जो बिल्कुल भी नहीं हैं, सामाजिक असंतोष के

प्रभाव से समन्वित रूप से संबंधित हो सकते हैं, विशेष रूप से, जब अपराध दो प्रतिद्वंद्वी परिवारों के बीच घरेलू असंतोष के कारण हुआ है। और विशेष रूप से, आवेदक का परिवार, जहां मृतक की बहन की शादी आवेदक के भाई से हुई थी। इसलिए, अपीलकर्ता के अपनी पसंद का सबूत पेश करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से और भारत के संविधान के भाग III के तहत परिकल्पित मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी संदेह से परे आरोपों को स्थापित करने के उद्देश्य से एक संतुलन बनाने के बीच संतुलन बनाना, जिसे वर्तमान मामले की परिस्थितियों में भी आकर्षित किया जा सकता है।

22. इस न्यायालय का विचार है कि जिन परिस्थितियों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन सिद्धांतों पर विचार किया गया है, वे उन परिस्थितियों से अधिक थे जब यह बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ अपराध से संबंधित था, और जहां अपराध करने में भागीदारी की स्थापना, या आवेदक को सौंपी गई एक विशिष्ट भूमिका, यह एक ऐसा तथ्य था जिसे साक्ष्य का नेतृत्व करके निर्धारित और साबित करने की आवश्यकता थी या जहां बरी होने की संभावना थी, और इसका मूल रूप से आवेदक को अपनी बेगुनाही स्थापित करने के अवसर का लाभ उठाने में सक्षम बनाना था, जो कि मामला नहीं हो सकता है, जिसे परिस्थितियों की भाषा में पढ़ा जा सकता है क्योंकि यह वर्तमान मामले में शामिल है। जैसा कि आवेदक के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया है। हालांकि व्यापक रूप से इस अदालत ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों, जहां समाज के विरुद्ध अपराध में किसी व्यक्ति की संलिप्तता का तथ्य, एक ऐसा तथ्य है जिसके लिए साक्ष्यों की विस्तृत और विस्तृत सराहना की आवश्यकता होती है और जिसके लिए लंबे समय तक विचारण की आवश्यकता होती है, यह उन तथ्यों के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए मानदंड थे। लेकिन इस मामले में, चूंकि एफआईआर में लगाए गए आरोपों का सेट है , जो जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए आरोप–पत्र द्वारा किए गए निष्कर्षों और टिप्पणियों द्वारा समर्थित है, एफएसएल रिपोर्ट बंदूक की संलिप्तता के तथ्य को स्थापित करती है, जिसे आवेदक द्वारा अपराध की शिकायत के लिए इस्तेमाल किया गया था और यह था। उसके कब्जे से बरामद किया गया।

23. इस न्यायालय का प्रथम दृष्टया विचार है कि निर्णय के पैराग्राफ संख्या 18 में की गई टिप्पणियों के प्रकाश में, आवेदक के अपराध में दोषी पाए जाने की संभावना और संभावना होगी, और विशेष रूप से, फिर से ऊपर देखी गई बातों पर वापस लौट आएगा, एफआईआर में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के विशिष्ट सेट के आलोक में।

24. आवेदक की दूसरी जमानत याचिका के विरोध में विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी यानी पीडब्ल्यू 1 श्रीमती अर्चना, मृतक की बहन। हेड कांस्टेबल श्रीमती सरस्वती रतूड़ी, पीडब्ल्यू 3, उन्होंने लगातार अपना रुख बनाए रखा है, जैसा कि एफआईआर में आरोप लगाया गया

है, अपराध करने में आवेदक को सौंपी गई भूमिका से संबंधित है। इसलिए, आवेदक के खिलाफ अधिनियम शिकायत जिसके लिए उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है, यह नहीं कहा जा सकता है, कि यह आईपीसी की धारा 300 के तहत निहित प्रावधानों के दायरे से बाहर था, जिसे आवेदक के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया है।

25. यहां तक कि रिकवरी मेमो के अनुसार, जिस पर इस न्यायालय ने भी विचार किया था, आवेदक एसएसबीएल गन 12 बोर जिसकी संख्या 1968 की संख्या 2498 है, के साथ–साथ आवेदक के कब्जे से वरिष्ठ निरीक्षक द्वारा पाए गए खाली कार्टिज पर विचार करते हुए। इसके अलावा, इसका उपयोग 13 एफएसएल रिपोर्ट संख्या 741/20बीए3420 यानी दिनांक26 जून 2020 से अपराध में हथियार की भी पुष्टि हुई है, जिसमें एफएसएल, उत्तराखंड, देहरादून के उप निदेशक द्वारा व्यक्त की गई राय के अनुसार, बरामद बंदूक का उपयोग उस अपराध को अंजाम देने में किया गया था, जिसकी शिकायत एफआईआर में की गई थी। आवेदक के खिलाफ परीक्षण और स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया था, और एक निष्कर्ष निकाला गया था कि आग बंदूक से बनाई गई थी जिसे एफएसएल प्रयोगशाला के समक्ष परीक्षा के लिए रखा गया था।

26. आवेदक के वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक और फैसले का और उल्लेख किया था जैसा कि 2012 (खंड 1) एससीसी पेज 40, "संजय चंद्रा बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो" में बताया गया था, और विशेष रूप से, उन्होंने उक्त निर्णय के पैराग्राफ नंबर 19, 20, 21, 22, 24 और 25 का संदर्भ दिया है, जो इस प्रकार है कि–**पैराग्राफ संख्या–"19.** पहले श्री रावल, विद्वान एएसजी द्वारा प्रस्तुत एक मामूली मुद्दे से निपटें। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने सह–अभियुक्तों में से एक (शरद कुमार बनाम सीबीआई (सुप्रा)) द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है और इसलिए, अपीलकर्ताओं के मामले में एक अलग दृष्टिकोण लेने के लिए परिस्थितियों में कोई कारण या बदलाव नहीं है, जिनके खिलाफ उसी अपराध के लिए आरोप पत्र भी दायर किया गया है। हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं। उपरोक्त याचिका में, याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने से पहले इस अदालत के समक्ष था। अब आरोप तय किए गए हैं और मुकदमा शुरू हो गया है। हम पहले और वर्तमान कार्यवाही की तुलना नहीं कर सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई बदली हुई परिस्थितियां नहीं हैं और इन याचिकाओं को खारिज करते हैं। **पैराग्राफ संख्या–20.** अपीलकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 420–बी, 468, 471 और 109 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ 13 (आई) (डी) के तहत अपराधों के संबंध में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। पहले विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, नई दिल्ली और बाद में उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। दोनों अदालतों ने उन कारकों को सूचीबद्ध किया है, जिन पर उन्हें लगता है कि आवेदकों द्वारा दायर जमानत आवेदनों को आरोप की गंभीरता के रूप में अस्वीकार करने के लिए

प्रासंगिक हैं; आरोप के समर्थन में सबूत की प्रकृति; दोषसिद्धि पर लगाए जाने वाले संभावित सजा; गवाहों के साथ हस्तक्षेप की संभावना; अभियोजन अधिकारियों की आपत्ति; न्याय से फरार होने की संभावना। **पैराग्राफ संख्या–21.** जमानत आवेदनों में, आम तौर पर, शुरुआती समय से यह निर्धारित किया गया है कि जमानत का उद्देश्य जमानत की उचित राशि द्वारा अपने मुकदमे में आरोपी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। जमानत का उद्देश्य न तो दंडात्मक है और न ही निवारक है। स्वतंत्रता से वंचित होना एक सजा माना जाना चाहिए, जब तक कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता न हो कि एक आरोपी व्यक्ति बुलाए जाने पर अपने मुकदमे का सामना करेगा। अदालतें इस सिद्धांत का मौखिक सम्मान करती हैं कि सजा दोषसिद्धि के बाद शुरू होती है, और यह कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि विधिवत मुकदमा नहीं चलाया जाता है और विधिवत दोषी नहीं पाया जाता है। **पैराग्राफ संख्या–22.** शुरुआती समय से, यह सराहना की गई थी कि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक हिरासत में हिरासत में रखना बहुत कठिनाई का कारण हो सकता है। समय–समय पर, आवश्यकता यह मांग करती है कि कुछ गैर–दोषी व्यक्तियों को मुकदमे में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मुकदमे के लंबित रहने तक हिरासत में रखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसे मामलों में, 'आवश्यकता' ऑपरेटिव टेस्ट है। इस देश में, यह संविधान में निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा के बिल्कुल विपरीत होगा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले के संबंध में दंडित किया जाना चाहिए, जिस पर उसे दोषी नहीं ठहराया गया है या किसी भी परिस्थिति में, उसे केवल इस विश्वास पर अपनी स्वतंत्रता से वंचित किया जाना चाहिए कि यदि वह स्वतंत्रता में छोड़ दिया जाता है तो वह गवाहों के साथ छेड़छाड़ करेगा। **पैराग्राफ संख्या–24.** इस मामले में, जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ "आरोप की उंगली उठाना" 'आरोप की गंभीरता' है। जिन अपराधों का आरोप लगाया गया है वे आथक अपराध हैं जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। हालांकि, उनका तर्क है कि अपीलकर्ताओं द्वारा गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना है, लेकिन उन्होंने आरोप के समर्थन में कोई सामग्री नहीं रखी है। हमारे विचार में, जमानत आवेदनों पर विचार करते समय आरोप की गंभीरता, निस्संदेह, प्रासंगिक विचारों में से एक है, लेकिन यह एकमात्र परीक्षण या कारक नहीं हैः दूसरा कारक जिस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, वह सजा है जो भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दोनों के तहत परीक्षण और दोषसिद्धि के बाद लगाई जा सकती है। यदि पूर्व ही एकमात्र परीक्षण है, तो हम संवैधानिक अधिकारों को संतुलित नहीं करेंगे, बल्कि "न्याय के पैमानों को फिर से अनुकूलित करेंगे। **पैराग्राफ संख्या–25**. सीआरपीसी के प्रावधान आपराधिक न्यायालयों को मुकदमे के लंबित या दोषसिद्धि के खिलाफ अपील में आरोपी को जमानत देने के लिए विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र प्रदान करते हैं, क्योंकि अधिकार क्षेत्र विवेकाधीन है, इसलिए

इसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल्यवान अधिकार और समाज के हित को संतुलित करके बहुत सावधानी और सावधानी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। हमारे विचार में, विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया तर्क, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, हमारी राय में, हमारी कानून प्रणाली और जमानत प्रणाली के सामान्य शासन के पूरे आधार से इनकार करता है। यह इस आवश्यकता के लिए सम्मान से परे है कि एक आदमी को निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह दोषी नहीं पाया जाता है। यदि ऐसी शक्ति को मान्यता दी जाती है, तो यह अराजक स्थिति पैदा कर सकता है और किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरे में डाल देगा।

27. उक्त मामले में, जिस पर मुकदमा चलाया जा रहा था और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार का विषय था, एक बार फिर एक ऐसा मामला था जो आईपीसी की धारा 420 बी, 468, 471, 109 और धारा 13 (2) के तहत अपराधों से संबंधित था, जिसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के साथ पढ़ा जाना था। और उक्त अपराधों के लिए मुकदमा चलाए जाने के लिए किसी अभियुक्त की जमानत से निपटने के पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए इसमें निर्धारित मापदंडों को एक समान पायदान पर नहीं रखा जा सकता है, खासकर जब मुकदमा, जिसे आवेदक के खिलाफ लेने पर विचार किया गया है, जघन्य अपराध यानी आईपीसी की धारा 302 के संबंध में है। जैसा कि इस मामले में शामिल है और अनुपात के आलोक में जमानत पर विचार करने के लिए अदालतों द्वारा अपनाए जाने वाले मानदंड, जो राज्य के खजाने को नुकसान के परिणामस्वरूप आर्थिक अपराधों से संबंधित है, को आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के खिलाफ नहीं तौला जा सकता है और यही कारण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पैराग्राफ संख्या 24** में अंतर किया गया है। संजय चंद्रा (सुप्रा) के निर्णय में कहा गया है कि उक्त मामले में आर्थिक अपराधों के संबंध में जमानत पर विचार करने के लिए किस परीक्षण को संतुष्ट करने की आवश्यकता होगी, जो उसमें विचार का विषय था।

28. उपरोक्त और विशेष रूप से उन कारणों के मद्देनजर, जिन पर इस न्यायालय ने एफआईआर की सामग्री की सराहना करते हुए पहले ही विचार किया है, विशेष रूप से इरादे, पूर्व नियोजित मन, किए जा रहे कृत्य के परिणामों के ज्ञान से संबंधित, स्पष्ट रूप से आवेदक के लिए सीधे जिम्मेदार था, इस न्यायालय का विचार है कि इस संभावना से परे इसे खारिज नहीं किया जा सकता है, कि मुकदमे के समापन पर आवेदक की संभावना होगी, उसके खिलाफ अपराध स्थापित हो सकते हैं, और चूंकि यह एक जघन्य अपराध है, जिसके द्वारा देखा गया है। मृतक की बहन, और अभियोजन पक्ष के अन्य गवाह, जिनसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष पूछताछ की गई है, और चूंकि शेष गवाहों की संख्या 19 है, अभी तक पूछताछ नहीं की गई है। इस न्यायालय का विचार है कि मुकदमे के इस चरण में आवेदक, जहां अपराधों की भागीदारी में उसकी प्रत्यक्ष भागीदारी

आसपास के तथ्यों, परिस्थितियों और सबूतों से स्थापित होती है, जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

29. इसलिए, आवेदक की दूसरी जमानत याचिका किसी भी नए आधार की आपूर्ति नहीं करती है, जिसे दूसरी जमानत याचिका पर विचार करते समय उद्यम करने की आवश्यकता होती है, इस प्रकार, दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है।

30. तर्कों का यह विस्तृत विचार, इस न्यायालय के लिए अपरिहार्य हो गया, क्योंकि वकील ने ऊपर दिए गए मुद्दों पर संबोधित किया था, और इस न्यायालय द्वारा उसी पर तर्क आमंत्रित किया था, इसलिए न्यायिक औचित्य और अनुशासन के लिए इस न्यायालय द्वारा तर्कों पर विचार करने की आवश्यकता थी।

31. हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि आज के आदेश में इस न्यायालय द्वारा जो भी कारण सौंपे गए हैं, वे प्रकृति में विशेष रूप से अस्थायी हैं, केवल वर्तमान जमानत आवेदन पर विचार करने के प्रयोजनों के लिए, कोई भी तर्क विशुद्ध रूप से अस्थायी प्रकृति का है, और ट्रायल करते समय ट्रायल कोर्ट के दिमाग को पूर्वाग्रह नहीं करेगा, जिसे स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाया जाना है।

(शरद कुमार शर्मा, जे.)

26.04.2022

एनआर/